

# प्लान-इट गर्ल्स: भारत में किशोरियों का सशक्तिकरण और रोजगार क्षमता बढ़ाना



प्लान-इट गर्ल्स बहुस्तरीय और बहुपक्षीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य किशोरियों की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर जेंडर समानता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम सामाजिक-पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर आधारित है, जा दिल्ली और झारखंड (भारत) के दो जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं व 11वीं में पढ़ने वाली किशोरियों को, जेंडर-समन्वित जीवन कौशल (उपयोगी हुनर) प्रशिक्षण और रोजगार क्षमता बढ़ाने के पाठ्यक्रम का उपयोग

करता है। यह कार्यक्रम कई स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है, जिसके तहत, स्कूलों के प्रिंसिपल्स व शिक्षकों, बच्चों के माता-पिता, समुदाय के लोगों, उद्योग जगत के अग्रणी लोगों व नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम किया जाता है ताकि ऐसा वातावरण बनाया जा सके जो लड़कियों के लिए मददगार हो और उन्हें अपनी आकांक्षाएं व लक्ष्य हासिल करने में सहायता करे।

## संक्षेप में जानने योग्य तथ्य

राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादातर राज्यों में, स्कूलों में लड़कियों के दाखिले का सकल अनुपात लड़कों से थोड़ा कम है। (<http://mhrd.gov.in/gross-enrolment-ratio-boys-and-girls>)

भारत में महिलाओं की श्रमिक भागीदारी 2004-05 में 42.7 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 31.1 प्रतिशत रह गई। महिलायें ज्यादातर ऐसे कामों में पायी जाती हैं जिनमें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता। (आइएलओ, जुलाई 2016)

उद्देश्य	रणनीति
उ.1	लड़कियों की आत्म क्षमता और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्कूलों में P.A.C.E. पाठ्यक्रम शामिल करना – जो दिल्ली में क्रियान्वित और मूल्यांकित PAGE पाठ्यक्रम – पर आधारित है ।
उ.2	लड़कियों की सफलता के प्रति विरोध को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और समुदाय में किशोर लड़कों, लड़कियों के परिवार और उनके समाज के लोगों की सहभागिता वाले कार्यक्रम संचालित करना ।
उ.3	शिक्षकों को कार्यक्रम में सहयोग देने और तत्पश्चात कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करना। साथ ही शिक्षकों को समर्थक (चौपियंस) और बदलाव लाने वाले एजेंट्स बनने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समान सोच रखने वाले एक नेटवर्क में एक दूसरे से जोड़ना ।
उ.4	किशोरियों को रोजगार सम्बंधित आवश्यक मंच व मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु स्थानीय कारोबार व उद्योगों के साथ आपसी तालमेल बनाना ।
उ.5	भविष्य में कार्यक्रम के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा फंड मुहैया कराने हेतु सरकारी शिक्षा तंत्र व उद्योगों के बीच संपर्क कायम करना ।
र.1	• आत्म क्षमता विकास, संसाधन जुटाने की क्षमता, रोजगार क्षमता व उद्यमशीलता का विकास करने हेतु स्कूलों में दो साल के दौरान किशोरियों के साथ 34 घंटों का पाठ्यक्रम संचालित करना ।
र.2	• दो शैक्षणिक सत्रों के दौरान, 25 घंटों का GEMS पाठ्यक्रम किशोर सहपाठियों के साथ क्रियान्वित करना । • माता पिता व समुदाय के अन्य लोगों को कार्यक्रम में शामिल करना ।
र.3	• विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के साथ विचारों का आदान प्रदान । • चुनिंदा शिक्षकों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करना ताकि अग्रणी नेतृत्व तैयार किया जा सके । • कक्षा में पढ़ाने की नई जेंडर संवेदनशील पद्धतियों को समर्थन देना ।
र.4	• उद्योग जगत के साझेदारों के साथ तालमेल बनाना ताकि किशोरियों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ें, उन्हें नेटवर्क से जोड़ा जा सके और उचित मार्गदर्शन मिल सके ।
र.5	• कार्यक्रम के द्वारा निजी क्षेत्र व सरकार को प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराना ताकि कार्यक्रम को नियमित और वृहत स्तर पर संचालित किया जा सके ।

वर्तमान में इस कार्यक्रम की पहुँच कक्षा 9वीं व 11वीं की 10000 किशोरियों तक है जिसमें 8000 किशोरियाँ दिल्ली के शहरी क्षेत्रों और 2000 झारखंड के दो जिलों – पाकुड़ और देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। लड़कियों के लिए तैयार किया गया 34 घंटे का पाठ्यक्रम दो शैक्षणिक सत्रों तक संचालित किया गया है जो मुख्य रूप से निम्न विषयों पर केंद्रित है:

- किशोरियों में अपनी पहचान व सजगता पैदा करना, उन्हें जेंडर के मुद्दों, सत्ता व पितृसत्ता, शारीरिक व भावनात्मक मुद्दों और रिश्तों के बारे में जागरूक करना ।
- आत्म क्षमता का विकास, संप्रेषण क्षमता, सत्ता व संबंध और हिंसा को समझना ।
- संसाधन क्षमता – जेंडर और आकांक्षाएँ, आकांक्षाओं का मानचित्र तैयार करना, जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना और कौशल/हुनर विकसित करना ।
- रोजगार क्षमता को बढ़ाना – रोजगार/नौकरी के लिए तैयारी, कार्य प्रबंधन क्षमता और उद्यमशीलता विकसित करना ।

लड़कियों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सक्षम बनाने के लिए किशोर सहपाठियों के साथ GEMS पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करना। साथ ही, माता पिता व समुदाय के अन्य सदस्यों को बैठकों व प्रचार अभियानों के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल करना ।

इस कार्यक्रम को सरकारी स्कूल तंत्र के साथ समन्वित किया गया है, कार्यक्रम व लड़कियों की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि स्कूलों के प्रिंसिपल व शिक्षकों के साथ विधिवत रूप से विचारों का आदान-प्रदान किया जाए। शिक्षक इस कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ और बदलाव के वाहक बनें, इसके लिए उन्हें पूरा समर्थन दिया जाता है ।

प्लान-इट गर्ल्स कार्यक्रम लड़कियों को भविष्य में शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करता है ताकि वे कौशल/हुनर हासिल करके उन्हें जीवन में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि कौशल प्रशिक्षण, उद्योग और सरकारी कार्यक्रमों व संसाधनों के बीच तालमेल स्थापित किया जाए। साथ ही, सरकार व उद्योगों के साथ विचार-विमर्श जारी रहेगा ताकि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इन कार्यक्रमों को नियमित और वृहत स्तर पर संचालित किया जा सके ।

इस कार्यक्रम को, ICRW के पार्टनर्स Students Partnership Worldwide, जिसका लोकप्रिय नाम है **Restless Development** और **Pravah** के सहयोग से, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली जिले के एजूकेशन जोन 29 में 10 सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूलों (लड़कियों और लड़कों दोनों) और झारखंड के देवघर व पाकुड़ जिलों के 10 सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूलों में संचालित किया जा रहा है ।